

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



25th October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

25th October 2022

1. - राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा:	3
(i) के बारे में:	3
(ii) कार्यान्वयन:	3
(iii) महत्व:	3
2. - पीएमएवाई:.....	4
(i) के बारे में:	4
(ii) लाभार्थी:.....	4
3. - एनएससीएन आईएम:	5
(i) एनएससीएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?	5
(ii) एनएससीएन-मुख्य आईएम से कौन से भाव जुड़े हैं?	5
(iii) क्या सरकार और नागा गुटों के बीच कभी शांति समझौता हुआ है?.....	6
4. - पृथ्वी की निचली कक्षा:.....	7
(i) के बारे में:	7



संपादकीय विश्लेषण..... 8

1. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम: 8

- (i) के बारे में: 8
- (ii) विदेशी दान प्राप्त करने के लिए कौन योग्य नहीं है? 8
- (iii) विदेश से धन प्राप्त करने के लिए मेरे पास और क्या विकल्प हैं? 8
- (iv) पंजीकरण कब रद्द या निलंबित हो जाता है? 9
- (v) एफसीआरए की क्या आलोचनाएं हैं? 9
- (vi) विदेशी अंशदान (विनियमन संशोधन) अधिनियम, 2020 ने कौन सी नई सीमाएँ जोड़ीं? 9

2. भारतीय प्रतियोगिता आयोग:..... 10

- (i) अधिक प्रतिस्पर्धी बनें: 10
- (ii) यह कानून क्या मना करता है: 10
- (iii) के बारे में: 10
- (iv) अध्यक्ष और अन्य सभी समिति के सदस्यों को निपुण, नैतिक रूप से शुद्ध लोग होना चाहिए जो: 10
- (v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लक्ष्य इस प्रकार हैं: 11
- (vi) प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग: 11
- (vii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के कर्तव्यों में शामिल हैं: 11



1. - राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा:

GS II

विषय→सामाजिक मुद्दे

➤ संदर्भ:

- मूलभूत उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक "जैविक" और "अच्छी तरह से तैयार" ढांचा प्रदान करती है, लेकिन पर्याप्त ढांचागत समर्थन और शिक्षक तैयारी के बिना इसका कार्यान्वयन मुश्किल होगा।

के बारे में:

- नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) का उद्देश्य हमारे स्कूलों और कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के दृष्टिकोण को जीवंत करके देश भर में उत्कृष्ट शिक्षण और सीखने को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना है।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि मंडेट ग्रुप की सहायता से और डॉ. के. कस्तुरीरंगन के निर्देश से है।

कार्यान्वयन:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के हिस्से के रूप में चुने गए 25 क्षेत्रों/विषयों में जिला-स्तरीय परामर्श, मोबाइल ऐप सर्वेक्षणों के परिणाम और राज्य फोकस समूहों द्वारा तैयार किए गए स्थिति पत्रों के आधार पर, सभी राज्य

और केंद्र शासित प्रदेश पहले अपने राज्य पाठ्यचर्या ढांचे का निर्माण करेंगे। (एनसीएफ)।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त संगठन और शिक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले संगठन एनसीएफ को इनपुट प्रदान करेंगे।
- विभिन्न हितधारकों से पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, NCERT MyGov पोर्टल पर एक सर्वेक्षण करेगा।

महत्व:

- कौशल विकास, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, मातृभाषा सीखने, सांस्कृतिक जड़ता और समग्र बाल विकास पर इसके जोर को देखते हुए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीएफ के विकास के लिए जनादेश दस्तावेज़ दिशानिर्देशों को उपनिवेशवाद की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के।
- नए NCF पर आधारित पाठ्यक्रम सुधार की समय सीमा 28 फरवरी, 2023 है, जैसा कि मंडेट ग्रुप द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- औद्योगीकरण, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद सभी का दुनिया पर प्रभाव पड़ा; परिणामस्वरूप, भारत दो शताब्दियों तक ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश रहा।
- स्रोत→हिन्दू



2. - पीएमएवाई:

GS II

विषय→सरकारी योजनाएं:

➤ संदर्भ:

- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) आवास योजना के तहत अधिकृत आधे से अधिक घरों को पहले ही वितरित किया जा चुका है। अन्य घरों का निर्माण अलग-अलग चरणों में है।

के बारे में:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित एक सरकारी कार्यक्रम, 2022 तक सभी के लिए आवास का हिस्सा है। (एमओएचयूए)।
- यह शहरी गरीबों को ईएमआई भुगतान (समान मासिक किस्तों) के दौरान आवास ऋण की ब्याज दर पर छूट प्रदान करके उन्हें वहन करने में मदद करता है।

लाभार्थी:

- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी समूहों के व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, मिशन शहरी आवास की कमी पर केंद्रित है।
- कम आर्थिक समृद्धि वाला क्षेत्र: एक परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रु. 3,00,00.

- निम्न आय समूहों (एलआईजी) और मध्यम आय समूहों (एमआईजी I और II) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा रु. 6,00,000 और रु. क्रमशः 18,00,000।
- एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और कोई भी बेटियाँ या बेटे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है।
- स्रोत→हिन्दू



3. - एनएससीएन आईएम:

GS III

विषय→आंतरिक सुरक्षा:

➤ संदर्भ:

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक मुइवा (एनएससीएन-आईएम), जिसने भारत सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू की है, और नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) की कार्यकारी समिति, जो नागालैंड के सात विद्रोही समूहों का एक छाता संगठन है, ने पिछले दिनों मुलाकात की। शांति समझौते की मध्यस्थता के प्रयास में सप्ताह।

एनएससीएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

- चूंकि शिलांग समझौता नागा संप्रभुता के मुद्दे को संबोधित नहीं करता था और उन्हें संविधान को अपनाने की आवश्यकता थी, एनएनपीजी के कई शीर्ष अधिकारियों और बर्मा से बाहर काम करने वालों ने इसे खारिज कर दिया।
- तीन एनएनपीजी नेताओं ने सशस्त्र आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1981 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) की स्थापना की। वे मणिपुर के उखरुल जिले के थुइंगलेंग मुइवा तांगखुल नागा कबीले के थे।
- इसाक चिशी स्वी और एसएस खापलांग क्रमशः सेमा और हेमिस जनजाति से हैं।

- एनएससीएन के मिशन वक्तव्य के अनुसार, भारतीय अधिकार से मुक्त एक जनवादी गणराज्य नागालैंड की स्थापना ईसाई सिद्धांतों पर की जाएगी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए समाजवाद का उपयोग किया जाएगा।
- केवल 150 संस्थापक सदस्यों के साथ, एनएससीएन तेजी से 3,000 सदस्यों तक बढ़ गया, जिनमें से अधिकांश कोन्याक और तंगखुल नागा जनजातियों के थे।
- लंबी आंतरिक उथल-पुथल, पर्याप्त अंतरजातीय संघर्ष और आंदोलन के मुख्य लक्ष्य के बारे में विवादों के कारण, एनएससीएन 1988 में दो संगठनों में विभाजित हो गया।
- NSCN-IM और NSCN-K का नेतृत्व क्रमशः इसाक चिशी स्वी, थुइंगलेंग मुइवा और एसएस खापलांग ने किया था।
- 1990 में श्री फ़िज़ो की मृत्यु के बाद NNC को भंग कर दिया गया था, और NSCN-IM सबसे शक्तिशाली विद्रोही समूह के रूप में जाना जाने लगा। इसने अन्य राज्यों में छोटे गुटों के उद्भव में भी सहायता की।

एनएससीएन-मुख्य आईएम से कौन से भाव जुड़े हैं?

- यदि वे सभी वहां (एक संप्रभु राज्य) रहते हैं, तो 1.2 मिलियन की नागा आबादी के साथ ग्रेटर नगालिम पूर्वोत्तर में अंतिम क्षेत्र होगा। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार के कुछ हिस्सों को कवर किया गया है।
- नागा येज़ाबो नागा लोगों (संविधान) का राष्ट्रीय ध्वज है।



क्या सरकार और नागा गुटों के बीच कभी शांति समझौता हुआ है?

- नागा क्षेत्र के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए भारत सरकार ने 1997 में एनएससीएन-आईएम को युद्धविराम के लिए राजी किया।
- अंत में, 1998 में, NSCN-K दो महीने के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गया; इस समझौते को बाद में अक्सर पूरे वर्षों में बढ़ा दिया गया था। केंद्र ने शुरू में एनएससीएन-के को किसी भी वार्ता या संघर्ष विराम समझौते में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
- 2015 के संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के बाद, एनएससीएन-के एक विस्तार के लिए सहमत हो गया।
- 1997 में एनएससीएन-आईएम के संघर्ष विराम के बाद से, केंद्र और विद्रोही समूह के बीच सौ से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है।
- एनएससीएन-आईएम और नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप (एनएनपीजी), जो एनएससीएन और कम से कम सात अन्य चरमपंथी संगठनों से बने हैं, ने नई दिल्ली (के) के साथ शांति वार्ता शुरू की है।

• स्रोत→हिन्दू



4. - पृथ्वी की निचली कक्षा:

GS III

विषय→विज्ञान और तकनीक

➤ संदर्भ:

- रविवार तड़के, भारत के सबसे बड़े रॉकेट ने एक चुनौतीपूर्ण मिशन को पूरा करने के बाद ब्रिटेन के एक ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों की सफलतापूर्वक परिक्रमा की, जिसमें कई प्रथम शामिल थे। इस मिशन की उपलब्धि वाणिज्यिक उपग्रह क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसरो की स्थिति को मजबूत करती है।

के बारे में:

- जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) एक कक्षा है जो पृथ्वी की सतह के काफी करीब है। यह अक्सर पृथ्वी से 1000 किमी से भी कम होता है, भले ही यह 160 किमी जितना कम हो, जो अन्य कक्षाओं की तुलना में कम है लेकिन फिर भी ग्रह की सतह से बहुत अधिक है।
- यहां तक कि सबसे कम LEO भी उससे दस गुना अधिक है क्योंकि अधिकांश वाणिज्यिक विमान 14 किमी से अधिक ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरते हैं।
- LEO उपग्रहों को हमेशा GEO उपग्रहों की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें हमेशा भूमध्य रेखा के पास परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोण वाले LEO उपग्रह

विमानों की संभावना है। नतीजतन, LEO उपग्रह पथों के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है, जो कि एक लोकप्रिय कक्षा होने का एक कारण है।

- LEO के कई फायदे हैं क्योंकि यह पृथ्वी के कितना करीब है। यह वह कक्षा है जिसका उपयोग उपग्रह फोटोग्राफी के लिए सबसे अधिक बार करते हैं क्योंकि यह सतह के करीब है और उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ तस्वीरें खींच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस), जो इसी तरह इस कक्षा में है, इंसानों द्वारा अधिक तेज़ी से और आसानी से पहुँचा और छोड़ा जा सकता है। चूंकि इस कक्षा में उपग्रह लगभग 7.8 किमी/सेकेंड की गति से चलते हैं और पृथ्वी की एक कक्षा को 90 मिनट में पूरा कर सकते हैं, आईएसएस प्रति दिन ग्रह की 16 कक्षाओं को पूरा करता है। उनके त्वरित आकाश आंदोलन और ग्राउंड स्टेशनों के लिए उनका पता लगाने में कठिनाइयों के कारण, व्यक्तिगत LEO उपग्रह दूरसंचार जैसे संचालन के लिए कम सहायक होते हैं।

- स्रोत→इंडियन एक्सप्रेस



संपादकीय विश्लेषण

विदेशी दान प्राप्त करने के लिए कौन योग्य नहीं है?

1. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम:

के बारे में:

- विदेशी दान को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डालते हैं, एफसीआरए की शुरुआत 1976 में हुई थी।
- प्राप्तकर्ताओं द्वारा अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी दान का उपयोग किया जाना चाहिए।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके कार्यान्वयन का प्रभारी है।
- सभी एसोसिएशन, एनजीओ और संगठन जो विदेशों से दान मांगना चाहते हैं, उन्हें एफसीआरए का पालन करना चाहिए। इनमें से प्रत्येक एनजीओ को हर पांच साल में एफसीआरए के साथ फिर से पंजीकरण कराना होगा।
- जवाबदेही: सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से मान्यता प्राप्त समूहों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दान स्वीकार किए जा सकते हैं। आवश्यक वार्षिक रिटर्न आयकर रिटर्न से मिलते जुलते हैं।
- व्यक्तियों, संघों या व्यवसायों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को मानकीकृत करने और देश के हितों के लिए हानिकारक कार्यों के लिए ऐसे योगदान के उपयोग को प्रतिबंधित करने के प्रयास में 2010 में कानून को संशोधित किया गया था।

- राजनीतिक दल के सदस्य, न्यायाधीश, न्यायविद और सरकार के कार्यकर्ता किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित हैं।
- एमएचए द्वारा 2017 में वित्त विधेयक प्रक्रिया के माध्यम से एफसीआरए कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलने के बाद, राजनीतिक दल अब एक विदेशी निगम की भारतीय सहायक कंपनी या एक विदेशी कंपनी से धन एकत्र कर सकते हैं जिसमें एक भारतीय के पास 50% या अधिक शेयर हैं।

विदेश से धन प्राप्त करने के लिए मेरे पास और क्या विकल्प हैं?

- यदि आप अन्य स्रोतों से योगदान स्वीकार करना चाहते हैं तो पिछली सहमति प्राप्त करना तीसरा विकल्प है।
- यह किसी विशेष परियोजना या गतिविधि को पूरा करने के लिए एक निश्चित स्रोत से धन के बदले में प्रदान किया जाता है।
- कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संगठन को लागू कानून के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए, जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, या 1860 का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम।



पंजीकरण कब रद्द या निलंबित हो जाता है?

- एक एनजीओ के वित्तीय उल्लंघन: एमएचए के पास संगठन के वित्त की समीक्षा करने और प्रबंधन से संबंधित किसी भी चिंता को ध्यान में रखते हुए 180 दिनों के लिए एफसीआरए पंजीकरण को अस्थायी रूप से निलंबित करने की शक्ति है।
- एनजीओ कामकाज पर प्रतिबंध: जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक एसोसिएशन को किसी भी नए दान को स्वीकार करने या निर्दिष्ट बैंक खाते में 25% से अधिक धनराशि खर्च करने की अनुमति नहीं है।
- अगर सरकार को लगता है कि एनजीओ को उपहार "सार्वजनिक हित" या "राज्य के आर्थिक हित" को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, तो उसके पास प्राधिकरण को अस्वीकार करने की क्षमता है।

एफसीआरए की क्या आलोचनाएं हैं?

- क्योंकि वे लोगों को आवाज उठाने और उनके हितों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, गैर सरकारी संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि लोकतांत्रिक कार्य करने की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया तो लोकतंत्रों को निश्चित रूप से नुकसान होगा।
- मौलिक अधिकार प्रभावित: एफसीआरए सीमाओं का स्वतंत्र भाषण और संघ के अधिकारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है जो क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(सी) द्वारा संरक्षित हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन संशोधन) अधिनियम,

2020 ने कौन सी नई सीमाएँ जोड़ीं?

- ऐसे भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की शाखाओं में, केवल बैंक द्वारा एफसीआरए खातों के रूप में मान्यता प्राप्त खातों को ही विदेशी दान स्वीकार करने की अनुमति है।
- यह एकमात्र खाता होना चाहिए जिसका उपयोग किसी भी विदेशी मुद्रा को स्वीकार करने के लिए किया जाता है।
- हालांकि, प्राप्तकर्ताओं को उपरोक्त किसी भी व्यवसाय में दूसरा एफसीआरए बैंक खाता खोलने और वहां प्राप्त धन को उपयोग के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति है।
- प्राधिकृत बैंक अपने स्रोत और प्राप्ति के तरीके के साथ प्रत्येक विदेशी हस्तांतरण के संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा।
- अधिनियम अनिवार्य करता है कि आधार संख्या का उपयोग सभी अधिकारियों, निदेशकों और विदेशी दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा पहचान के कारणों के लिए किया जाए।
- कुल प्राप्त विदेशी दान का केवल 20% अब प्रशासनिक लागतों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो कि उस राशि में कमी है जिसे पहले अनुमति दी गई थी। 2010 के FCRA द्वारा 50% कैप की शुरुआत की गई थी।



2. भारतीय प्रतियोगिता आयोग:

- राघवन समिति के प्रस्ताव पर, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अधिक प्रतिस्पर्धी बनें:

- आधुनिक प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर आधारित हैं, जैसा कि 2007 के प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम द्वारा अद्यतन किया गया है।

यह कानून क्या मना करता है:

- समझौते जो प्रतिद्वंद्वियों के लिए अनुचित हैं
- अनुकूल स्थिति का व्यावसायिक दुरुपयोग

के बारे में:

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन संशोधन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था।
- 20 मई, 2009 को, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधान और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था।

- अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अब एक अध्यक्ष और छह सदस्य हैं।

अध्यक्ष और अन्य सभी समिति के सदस्यों को निपुण, नैतिक रूप से शुद्ध लोग होना चाहिए जो:

- उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए मानदंडों को पूरा करता है, या
- किसी भी क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता और कम से कम पंद्रह साल का प्रासंगिक अनुभव है, जो केंद्र सरकार का मानना है कि आयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों और प्रशासन सहित उपयोगी हो सकता है।
- आयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को समाप्त करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और भारतीय बाजारों में व्यापार स्वतंत्रता की गारंटी देने का प्रभारी है।
- इसके अतिरिक्त, किसी भी कानून द्वारा बनाए गए सरकारी संगठन के अनुरोध पर, आयोग प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाएगा और उन विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- वैधानिक प्राधिकरणों को अर्ध-न्यायिक आयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो अन्य मुद्दों से भी निपटता है।



भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

मजबूत संबंध स्थापित करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

- उपभोक्ता कल्याण में सुधार और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए भागीदारी और प्रवर्तन के लिए, एक आक्रामक, आविष्कारशील और नैतिक कॉर्पोरेट वातावरण बनाना और उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:

- सभी पक्षों, जैसे ग्राहकों, भागीदारों, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय संचार।
- एक ऐसी कंपनी होने के नाते जो शिक्षा और प्रशिक्षण को बहुत अधिक महत्व देती है
- व्यावसायिकता, खुलेपन, तप और ध्वनि निर्णय का प्रदर्शन

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के कर्तव्यों में शामिल हैं:

- ग्राहकों के पक्ष में कार्य करने के लिए बाजारों पर प्रभाव डालना।
- स्वस्थ, नैतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए समावेशी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना।
- प्रतिस्पर्धा के लिए नियम स्थापित करने से यह गारंटी मिलेगी कि उपलब्ध धन का यथासंभव प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्रीय नियामकों के नियम प्रतिस्पर्धा कानून का पालन करते हैं, उनके साथ

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

